**भारत सरकार**

**वस्त्र मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2555**

**8 अगस्त, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**वस्त्र क्षेत्र में संभावित वृद्धि किया जाना**

**2555. श्री संभाजी छत्रपतीः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क)** क्या वस्त्र उद्योगों के एक भाग ने यह प्रस्ताव किया है कि मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ), 10 प्रतिशत मार्जिन राशि तथा 9 माह की ऋण सीमा से भारतीय बुनकर मिलों को सूत के बहुराष्ट्रीय व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी;

**(ख)** कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के साथ तथा बी-टी कॉटन को लाये जाने के प्रस्ताव से किसानों को बेहतर मूल्य, जमाखोरी और सट्टेबाजी से बचाव तथा वर्तमान 6 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की विकास दर प्राप्ति की कितनी संभावना है;

**(ग)** क्या पीएसएफ और टीएमसी द्वारा कपास के उत्पादन में वृद्धि, और अधिक रोजगारों के सृजन, निर्यात संवर्धन तथा राजस्व की वसूली बढ़ने की संभावना है; और

**(घ)** यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वस्त्र राज्य मंत्री**

**(श्री अजय टम्टा)**

**(क) से (घ):** कपास किसानों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से भारत सरकार कपास के उत्पादन को बढ़ाने, कपास के निर्यात को बढ़ावा देने और कपास के मूल्य स्थिरीकरण के लिए विभिन्न उपाय कर रही है:-

i. कपास मौसम (अक्तूबर से सितंबर) की शुरूआत से पूर्व प्रत्येक वर्ष कृषि मंत्रालय, भारत सरकार देश के कपास किसानों को प्रोत्साहन देने के मद्देनजर बीज कपास की दो किस्मों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। बेहतर उत्पादकता और उत्पादन सुनिश्चित करने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने मध्यम स्टेपल कपास और लंबे स्टेपल कपास के लिए वर्ष 2018-19 हेतु क्रमश: 28% और 26% तक एमएसपी में वृद्धि की है।

ii. कपास किसानों के बड़े वर्ग को एमएसपी के लाभ प्रदान करने और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सभी कपास उत्पादक राज्यों में जब कभी बीज कपास का मूल्य एमएसपी स्तर पर पहुंचता है, तो एमएसपी दरों पर विभिन्न एपीएमसी बाजार यार्डों में

कपास किसानों द्वारा पेश की गई कपास (एफएक्यू ग्रेड) की समग्र मात्रा की खरीद करने के लिए एमएसपी अभियान चलाने हेतु भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

iii. सीसीआई, अधिकतम कपास आवक को कवर करने के लिए कपास उत्पादक सभी राज्यों में हर वर्ष समुचित खरीद केंद्र खोलती है। चालू कपास मौसम के लिए सीसीआई ने 348 खरीद केंद्र खोले हैं और कपास किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कपास मौसम के पहले दिन से बाजार में सक्रिय है। वर्ष 2014-15 कपास मौसम में भारतीय कपास निगम द्वारा एमएसपी अभियान के अंतर्गत अब तक की सबसे अधिक 86.96 लाख गांठों की खरीद की गई थी।

iv. चालू कपास मौसम 2017-18 में 1 अगस्त, 2018 तक भारतीय कपास निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान और वाणिज्यिक अभियान के अंतर्गत बीज कपास की क्रमश: 3,89,825 गांठ और 6,80,415 गांठ की खरीद की है।

v. अक्तूबर, 2017 से अप्रैल, 2018 तक भारत से निर्यात की गई कपास की कुल मात्रा 51.21 लाख गांठ थी। कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) ने अनुमान लगाया है कि चालू कपास मौसम 2017-18 (अक्तूबर, 2017 से सितंबर, 2018) के दौरान भारत से कपास का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 20% तक बढ़ने की संभावना है और सितंबर, 2018 तक कपास का निर्यात 70 लाख गांठ तक पहुंचने की आशा है।

vi. सीसीआई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) की इकाइयों सहित घरेलू वस्त्र द्योग को ई-नीलामी के माध्यम से नियमित रूप से अपने स्टॉक को भी बेचती है। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग को न केवल अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्ता वाली कपास प्रदान की जाती है बल्कि बाजार को स्थायित्व भी प्रदान करती है।

vii. कपास प्रौद्योगिकी मिशन जिसे विपणन अवसंरचना के आधुनिकीकरण के साथ-साथ कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए फरवरी, 2000 में आरंभ किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखानों और बाजार यार्डों के आधुनिकीकरण से भारत में गुणवत्ता युक्त कपास का बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव हुआ। मैसर्स आईसीआरए की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी अवधि से पूर्व की 4-8% की अवशिष्ट सामग्री आधुनिकीकरण के पश्चात घटकर 1.5-3% हो गई।

viii. सरकार, प्रौद्योगिकी उन्न्यन निधि योजना, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, पॉवरटेक्स इंडिया, विद्युतकरघा क्षेत्र व्यापक योजना आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अंतर्गत कताई मिलों सहित वस्त्र इकाइयों को सहायता प्रदान कर रही है।

कपास के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****